श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : अन्य पार्टियों के तो एकएक को बुला लीजिए । कांग्रेस के जो ज्यादा हैं, उनको बुलाइये । . . . . **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : I am going to call you, Mathur Saheb.

Meanwhile, we have one more message from the Lok Sabha.

(ii) The Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 1992.

SECRETARY-GENERAL : Madam, I beg to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha :

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the ,Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 1992, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 12th May, 1992."

Madam, I lay the Bill on the Table. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : I did not encourage you. There was no encouragement from the Chair.

STATEMENT BY MINISTER

Provision of Group Dialling Facility in Rural Areas and Local and Rationalisation of Tariff for Local and Trunk Calls

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं सर्वप्रथम . . . **(व्यवधान)** . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : Sahu Saheb, just one minute. I would like to seek the permission of the House, since there is no other Vice-Chairman present, to call Mr. Narayanasamy kindly to take the Chair. J am also going to ask for clarifications.

SHRI BHUVNESH CHATURVEDI (Rajasthan): Madam, Vice-Chairman, it is a good replacement.

श्री रजनी रंजन साहू : आप मेरी बात सुन लीजिए । अब आपको उपसभाध्यक्ष महोदय कहना पड़ेगा ।

[Shri V. Narayanasamy in the Chair]

DR. RATNAKAR PANDEY (Uttar Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, are you going to allow every Member to speak or not ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Special mentions will be taken up tomorrow. 7.00 P.M.

DR. RATNAKAR PANDEY : Are you going to allow every Member or not. Please make it clear

THE VICE-CHAIRMAN SHRI V. NARAYANASAMY) : Special Mentions will be taken up tomorrow.

श्री रजनी रंजन साहू : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और धन्यावाद भी देता हूं कि इन्होंने यह महसूस किया कि देश में टेलीफोन के इस्तेमाल का कंसेप्ट क्या है । आज देश में टेलीफोन के इस्तेमाल का कंसेप्ट सिर्फ स्टेटस नहीं है, आवश्यकता है । इस बात का उन्हें अहसास है, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं । इन्होंने आपने स्टेटमेंट में कहा है कि ग्रामीण इलाकों में ग्रुप डायलिंग फैसिलिटीज की व्यवस्था और उसके टैरिफ में रेशनेलाइजेशन की बात की जाएगी ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसा देखा गया है कि टेलीफोन की बिलिंग व्यवस्था में ह्यूमन ऐरर होता है । कभी मीटर में गड़बड़ी होती है, कभी मीटर रीडिंग में गड़बड़ी होती है और जान-बूझकर कुछ गड़बड़ की जाती है और किसी का कनेक्शन किसी के साथ जोड़ दिया जाता है । एक रोता है, दूसरा हंसता है । इसलिए जो ग्रामवासी हैं उन्हें कठिनाईयों का सामना

करना पड़ेगा क्योंकि बहुत तेजी से आप ब्लाक और गांवों को जोड़ने जा रहे हैं ।

मंत्री महोदय मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनें । यह बड़ी अहम समस्या बन गई है । आप जिस स्पीड से टेलीफोन की व्यवस्था और कम्युनिकेशन की व्यवस्था का प्रचार-प्रसार कर रहे है उसमें यह दिक्कत बन सकती है क्योंकि ग्रामवासी जो हैं, उनको एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जब कभी उन्हें गलत बिल आ जाएगा, जब ऐक्सस बिल आ जाएगा। आज हमारे बहुत से माननीय सदस्य इस बात से परेशान हैं कि उन्हें ऐक्सस बिल आ रहा है । अभी हम लोग देखते हैं कि एक का कनेक्शन दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है । वह हंसता है जिसे फायदा होता है और यह रोता है जिसके ऊपर उसका भार पड़ता है । तो ग्रामीण, इलाकों में इन कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा । तो उसके लिए इनके पास क्या व्यवस्था है ?

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक कंज्यूमर फोरम बनाकर उनकी अनुशंसा पर जो गलत मीटर रीडिंग या गलत बिल आदि की समस्याएं उत्पन्न होंगी, उसके लिए एक क्यासी जुडिशियल कोर्ट बनाएंगे ताकि उस ब्लाक में ही ग्रामवासी उपनी बात कहकर उसका समाधान कर सकें ? क्या ऐसी कोई व्यवस्था

SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pradesh): The first thing that I want to know is this. The Minister has said that these schemes will be implemented by 31st August, 1992. I welcome the schemes and 1 contratulate him for a deep thinking in the matter. He wants to reach all the villages. I want to know what will be the total cost of the plan. How much would it cost the Exchequer ?

Secondly, though it)is rather technical, while talking of the revised charging plan, the Minister has observed at page 3, first sentence :

"Although this proposal will entail substantial loss to the Department, it is expected that with increase in telecommunications network, the same would be compensated in future."

1 would like to know what is the substantial loss because of this and how much will it be augmented and conpensated ?

Thirdly, certain concepts are not clear. For example, this Group Dialing business. It is rather technical. What is this Group Dialing concept ? Please enlighten on this. Of course, telephone facility is a good thing. As my hon. friend who preceded me said, when the telephone bills are inflated and come to us, then, it ceases to be good. I would also say even the Members of Parliament have complaints about inflated bills. Somebody gets a telephone bill of Rs. 2 lakhs. Somebody gets a telephone bill of 3 lakhs. Somebody even gets a bill of Rs. 8 lakhs. Perhaps the main source of inflated bills is the lower staff, technical staff who mix up the line and these troubles emanate from them. 1 do not know how it is done in the case of electronic telephone exchange. He must have received complaints to this effect from a number of people. 1 want to know what measures he is taking to satisfy, to remove these genuine complaints. Shri Rajesh Pilot is such a dynamic Minister and he is done so much tor the villages that 1 hope he will do something regarding inflated bills. If Members of Parliament are getting inflated bills, you can imagine the plight of the common man.

1 will end up with one small problem pertaining to my home town, Jaunpur. An electronic exchange equipment was brought over here. But I do not know why it was removed to another distant place. Though a decision was taken to install it in Jaunpur, they have moved it to another place. In this connection, I had asked a question in this House. Probably that question got mixed up with some other matter. The Minister thought that I was asking for a manual telephone exchange. In fact, I asked for an electronic telephone exchange. I want to know, why it was shifted to another

[Shri Kapil Verma]

place. One cannot get this district and Cities in Eastern Uttar Pradesh in the morning when the offices are open. You have to dial either in the night or in the morning. It becomes very difficult to contact Some offices. We cannot do our public work. I hope the Minister will throw some light on this.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन, सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय, को बधाई देता हूं कि इन्होंने काफी कोशिश करके टेलीफोन की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है। छोटी मोटी ऐफिशियेंसी भी प्राप्त की है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपने जो ग्रुप डाइलिंग किया है, इसका आब्जेक्टिव क्या है ? हवट इज इटस आब्जेक्टिव ? आपने घरबार की सुविधा हो या व्यापार में सुविधा हो या ऐडमिनिस्ट्रेडिव सुविधा हो, ला एंड आर्डर को कंट्रोल करने में सहायक हो सकता है ? मेरा कहना यह है कि जिस समय आप ग्रुप डाइलिंग के लिए एरिया तय करें तो उसमें आब्जेक्टिव मुख्यतः ला एंड आर्डर को कंट्रोल करने की दृष्टि से क्या हो सकता है, ऐसे एरियाज तय करने चलिए। इसी तरह से ऐडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए करना चाहिए। तो मुझे आप बता दें कि जब आप आपने तय किया कि गांव में टेलीफोन पहुंचाना है तो तफरी की ही बात है या क्या है ? मैंने दो तीन आब्जेक्टिव आपके सामने रखे हैं, उनकी आप व्याख्या कर दें।

अगर आप गांवों तक टेलीफोन पहुंचाना चाहते हैं तो आपको जो टेलीफोन का किराया है उसको कम करना होगा अन्यथा कस्बे में अमीर आदमी अथवा किसी खेत खलिहान के पास रहने वाला बड़ा किसान ही उसका उपयोग कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकेगा। तो मेरा प्रश्न यह है कि आप टेलीफोन के किराए में किसी प्रकार से कमी करने पर विचार करेंगे ?

तीसरे जब इतना विस्तार होगा तो . . .

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : माथुर साहब गांव में पहुंचने दीजिए पहले . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Mathurji, you can seek clarifications. Don't listen to them.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप गांवों तक पहुंचाना चाहते हैं तो किराये में कमी कीजिए।

इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आपने यह अनुमान लगाया है कि इससे कितने जॉब्स पैदा होंगे।

श्री शान्ति त्यागी : संचार मंत्री गांवों के हितैषी है . . . . **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : ये मुझसे जवाब मांग रहे हैं, मैं मंत्री थोड़ा हूं . . . **(व्यवधान)**

श्री शान्ति त्यागी : हो जाएंगे कभी . . .

(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : ये मेरा दुर्भाग्य कहां है कि मैं मंत्री बनूं और मुझे जवाब देना पड़े।

यह जानना चाहता हूं कि कितने अंदाज से जॉब पैदा होंगे और किस प्रकार से होंगे ? क्या इस प्रकार की ट्रेनिंग के लिए कोई व्यवस्था आपने की है ? अंतिम सवाल यह है कि आजकल जो फेक्स मशीन हैं, आपने लिखा है कि बहुत समय लगता है, बात ठीक है। लेकिन मेरी यह जानकारी है अगर गलत हो तो दुरुस्त कर दें कि फेक्स मशीन जहां लगती है उसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। हर कोई चला ले इसकी मैं इजाजत नहीं है। हालांकि चलाते सब ऐसे ही है। मेरा सुझाव है कि बजाय इसके आप डिस्टर्ब करें ऐसे एरियाज जहां पर फेक्स मशीन आप दे रहे हैं उनसे टेक्स ले लीजिये। जो फेक्स है उसको फ्री कर दीजिए जो चाहे खरीद ले कोई दिक्कत नहीं है लेकिन चैक नहीं कर सकते। मैं अगर एक फेक्स मशीन खरीद कर कार में ले जाता हूं और जिस गांव में टेलीफोन लगे हैं वहां लगाकर आपरेट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सुझाव है फेक्स मशीन पर जो आपने रुकावट लगाई है उसको छोड़ दीजिए। जो एस्टाबलिशमेंटस है जिन पर आपने यह किया है

यदि आप उन पर एक फिक्स रेट लगा दें तो यह सुविधाजनक हो जायेगा । आम आदमी तो फेक्स लगाता नहीं है । या तो बिजनैस कसंर्न लगाते हैं अथवा आर्गेनाइजेशन लगाते हैं उन पर बजाये इसको लगाने के आप फेक्स मशीन पर जो इसको लगायेगा उससे फिक्स रेट ले लीजिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Two minutes will be given for each Member because there are still twelve Members to seek clarifications. So, kindly be brief and raise poinfs only.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने ग्रामीण स्तर तक टेलीफोन की सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया है और 31 मार्च, 1995 तक दो लाख 20 हजार ग्रामीण पंचायतों तक यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी । साथ ही जो ग्रुप डायलिंग की सुविधा आपने देने का काम किया है वह भी अपने में एक महत्वपूर्ण काम है । एक बात जरूर है यह सब सुविधा देते हुए आपने अपने अंतिम पैरे में कहा है कि जो स्थानीय कॉलों की मल्टी-मीटरिंग होती है, हमने भी इसकी बहुत दिनों से मांग की थी और कंसलटेटिव कमेटी में भी इस बात को उठाया था, अच्छा हुआ आपने 3 मिनट से बढ़ाकर पल्स मीटरिंग को 5 मिनट का कर दिया है और 31-8-92 से पहले यह सारी व्यवस्था जो तकनीकी चीजें है, पूरी कर लेंगे और काम पूरा हो जायेगा । मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं । पहला यह कि बहुत बड़ा नेट वर्क है । दो लाख बीस हजार गांव तक यह सारी व्यवस्था 1992 तक पहुंच जाए यह सब आपको करना है । इस संबंध में जो टेलीफोन की व्यवस्था है जो अधिकारियों से संबंधित है विशेष रूप से क्षमता की जो आवश्यकता उसमें पड़ती है उस वजह से जैसा कि मेरे कुछ साथी आशंका व्यक्त कर रहे कि बिलिंग में गड़बड़ी हो जाती है तो मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखें, नहीं तो गांव वाले पिट जायेंगे । यह बहुत जरूरी है । दूसरी बात यह कि जो आप व्यवस्था करने जा रहे हैं इसमें कितने करोड़ रुपये लगने का अनुमान है ? जो इक्यूपमेंट आप इस्तेमाल करेंगे उसमें इंडिजनस कितने का और इम्पोर्ट कितने का करके उसकी व्यवस्था करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं । मेरी राय यह है कि अधिक से अधिक जो इंडिनस इक्यूपमैंट है उसका प्रयोग अगर किया जायेगा तो बहुत ही अच्छा होगा । इस आधार पर मैं मंत्री महोदय से इन तीन प्रश्नों को पूछना चाहता हूं । सब कर दीजिए तो अच्छा है ।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka) : Sir, I want to compliment the Minister on this. But I am unable to understand one clause. It is a technical point. I will be understanding it only when it pinches me. I will give you an example. It is about the rating. I am living 200 kilometres away from Bangalore. Earlier, I used to pay Rs. 25 as charges per metre-call. For a distance beyond 200 kilometres, it is Rs. 50. But they are charging me Rs. 50 though 1 am within 200 kilometres. When I took up the matter with the officials, they said, "You have been billed. That billing arrangement is made from Bangalore to the billing station which is 60 kilometres away." I do not know why I should pay double the charges just because the billing station is 60 kilometres away. Unless I know where it pinches, I am unable to persuade myself to compliment Mr. Rajesh Pilot. When it pinches me, then alone I will be able to understand. He himself said that this is more technical.

As far as the yardstick of the telephone is concerned, the Minister himself has accepted that it is no more a status symbol. It is a necessity. I request the Minister to keep a monitor at the district level or at the tehsil level to know as to how many phones the area is having, how many hours they are working in a day and for how many hours, they remain idle. Then we will know the real position. We need not be happy that we have extended the net-work for the whole country and a number of phones have been installed. But how

[SHRI H. HANUMANTHAPPA] many phones are really giving service'.' That is more important. I request the Minister to introduce a system wherein there is monitoring in every exchange and the mechanics concerned should be hauled up if the percentage of dead telephones is more or if the telephones are not working properly. I request him to take serious, note of it and introduce it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : I said, two minutes for each Member. You have crossed two minutes.

SHRI H. HANUMANTHAPPA : I am not repeating anything. Now, I repeat your request. If an auto-rickshaw can have a meter, if a taxi can have a meter, why can't the telephone ? Like the Electricity, Department, put a meter. Even if it is at our cost, it doesn't matter.

SHRI RAJESH PILOT: I will put a meter.

SHRI H. HANUMANTHAPPA : Thank you. At least for three minutes, let it be under our control. It should not be under the control of your department. In my own district, taluk headquarters is at a distance of forty kms. But the line via Arsikare covers a distance of 160 kms. The consumers have to pay charges for 160 kms rather than 40 kms. This anomaly should go. The Minister has assured us that the new system will take care of the removal of this anomaly.

Thirdly, the Minister has stated that electronically so many districts are being converted. I am from a district headquarters. In a district headquarters, you have connected only one-third or one-fourth of the telephones to electronic exchanges. Your old units still continue. You have connected new units. That does not mean that you have covered the whole district. The whole thing should come into this.

Fourthly, one more important aspect is there. Whenever there is a complaint, the department has a key with them. They stop the telephone first and say, first you pay and then complain, If you change this rule, your officers will learn a. lesson. Why do you penalise us ? There may be genuine difficulties, there may be genuine problems. In other cases, you fix a date and if there is a complaint, let it be decided within one week or within ten days. The department should decide it and take money. But the department says, first pay the full amount and then complain. This system should go. This system has given unlimited powers to the department and the subscribers have been hauled up unnecessarily.

After seeking these clarifications, I still compliment the Minister, of course, with a reservation that whenever it pinches me, I will speak.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन के बारे में पहली कम्प्लेन्ट यही होती है कि फैक बिल्स आते हैं। मैंने तो मंत्री महोदय को पटना का एक केस भी दिया था। वह छः दिनों का बिल था। उन छः दिनों का हिसाब मैंने घंटों में और घंटों से मिनटों में और मिनटों से सेकेन्डों में लगाया तो इन छः दिनों में 5 लाख 18 हजार 4 सौ सेकेन्ड होते थे। जो बिल दिया गया वह 10 लाख 47 हजार 560 रु० का था। अगर वह मीटर कंटीन्यूएसली चले तो भी इतने का बिल नहीं हो सकता था। वह मीटर डबल रेट से दौड़ रहा था। मंत्री जी की बड़ी कृपा हुई, अल्टीमेटली 34 हजार रूपये लेकर उनका टेलीफोन रेस्टोर किया गया। यह फरदर इस्टेब्लिश करता है और ऐसे केस इस्टेब्लिश करते हैं कि इसमें कुछ गलतियां हैं, इसमें सुधार करने की जरूरत है। मैं मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगा कि आप तो इसको इलेक्ट्रोनिक्स करने के लिए बहुत सारे सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीफोन को, ग्रुप डायलिंग को, गांवों तक ले जाने की कोशिश कर रहे है।

यहां केपिटल में, दिल्ली में हमारी नाक के नीचे पिछले हफ्ते किदवाई भवन जल गया। इससे आप अपनी मशीनरी कैसे बचा पाये ?

आपका 197 काम नहीं कर रहा है, आज दिल्ली में 171 काम नहीं कर रहा है, 199 काम नहीं कर रहा है। मुझे तो उस समय शाक लगा, धक्का लगा जब मैंने बड़ी मुश्किल से 197 नंबर पकड़ा तो वह महिला आपरेटर कहने लगी कि हमारा जितना कंप्यूटर रिकार्ड था, लेटेस्ट रिकार्ड वह जल गया है। मैं आपको मैनुअली डाइरेक्ट्री से पढ़कर नंबर बता सकती हूं क्या यह सच है? अगर सच है तो यह जो रिकार्ड का नुकसान हुआ है, इसके लिये कोई इंक्वायरी बिठाई या नहीं बिठाई कि किन कारणों से अलग आग लगी? जैसे पहले यहां विज्ञान भवन जल गया था परन्तु आज तक पता नहीं चला है कि आग कैसे लगी। वहां पर इतनी कीमती मशीनरी जल गई है लेकिन किसी को पता नहीं है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद यह मैनुअल से इलैक्ट्रानिक क्रास बार एक्सचेंज ग्रुप डाइलिंग सुविधा और एस. टी. डी. की सुविधा सहित पूरे देश को नेटवर्क देना यह बहुत अच्छा कदम है। यह कदम हमारे देश की प्रगति का बैरोमीटर है और यह बेसिक इन्फास्ट्रक्चर जो है यह देश की प्रगति के एक स्तम्भ के रूप में उभरेगा। पर उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन गांवों में या जिन तहसीलों में या जिन जिलों में 24 घंटों में से 20 घंटे बिजली नहीं रहती है वहां इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज को मेंटेन कराने के लिए एयर कंडीशनर कैसे चलायेंगे? और अगर एयर कंडीशनर नहीं चलायेंगे तो आप के जो ये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज है ये काम नहीं कर सकते तो यह जो एक्सचेंज बनेंगे ये हमारी ईंडियन क्लाइमिटिक कंडीशन को मैच करते हुए विदाउट एयरकंडीशन के चलेंगे क्या, इस तरह के हैं क्या? इस तरह की सुविधा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, इन्होंने वैसे तो ट्रैफिक को कम करने की बहुत भारी कोशिशें की हैं। पर आज भी चाहे मद्रास हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो और ईवन हमारा जो बेगूसराय हो, जहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, वहां भी अगर टेलीफोन करिये तो आता है कि हैवी ट्रैफिक आन दि लाइन ट्राई आफटर सम टाइम, लाइनें व्यस्त है, यही आता है। पंजाब की लाइनें, पटियाला बात करना चाहे, जालंधर बात करना चाहें तो टेलीफोन मिलेगा नहीं। बेगूसराय जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है वह भी नहीं मिलता है। इसमें सुधार लाने के लिये आप क्या कदम उठा रहे हैं? इनमें समय इसलिये लगता है क्योंकि मैनुअली चल रहे हैं। महोदय, जैसे कि सब सदस्यों ने मांग की है जिस तरह से बिजली का मीटर हमारे घर पर लगा होता है, पानी का मीटर घर पर लगा हुआ होता है, उसी तरह से टेलीफोन का भी मीटर घर पर लगा होना चाहिये, हर सब्सक्राइबर के घर पर लगा होना चाहिये ताकि उसको पता चले कि कितना प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan) : Mr. Vice-Chairman, I have always been pointing out that if the communication system is improved, it will really help the country, especially in saving petroleum. Therefore, I compliment the hon. Minister that this system is definitely improved, not only for local calls but for any type of calls, either international or national. The point I would like to raise is that they are going to meter calls only in electronic exchanges. When you meter one call for five minutes, it sounds to me discriminatory. How are you going to solve this problem ? There can be a legal problem if you say that simply because one is in an electronic exchange, one can talk for only five minutes for one call, and if one is not in an electronic exchange in the same State or in the same district or in the same area, one can go on talking for any length of time. How will you solve this problem ? There are some areas where electronic exchanges and other exchanges are functioning simultaneously. How is ha going to solve this problem ? This is my first question.

[SHRI SANTOSH BAGRODIA]

The second question is this. When international calls are made in other countries there are times fixed when less rates are charged, e.g., from 6.00 PM. to 10.00 P.M. half rates are charged for local calls and quarter rates for STD calls, as it is being done here. For international calls also there are different rates at different times in other countries. I would like to know from the hon. Minister whether he plans to have this kind of system for making international calls from India also or not. Another point, which I made in the morning during Question Hour, is; Why are calls for nearby countries not booked ? I don't know what is the logic behind it. If STD is not available, obviously the operator should help through the operator in that particular city or country. Why are these calls for neighbouring countries not allowed ? Will the Minister like to introduce that system now ?

When we come to the bills, my experience is that even M.Ps. are not getting the detailed bills of the calls made by them, even for STD calls. In the electronic exchanges it is available. But still it is not being given to the M.Ps. The officers in the Rajya Sahba Secretariat just give us one bill—so many calls, so much money. We go on asking for the details; they never give us the details,. If you can, please at least issue orders so that, like any other citizen of this country, the M.Ps. should also get the details.

As regards directory information, as Mr. Ahluwalia has said, how there may be some problem. Why should we not get directory information for all over the world ? With the present computer system it is possible. So, it must be introduced.

The last point which I would like to make is about collect-calls, which the Minister has mentioned in the morning. Collect-calls are allowed by other countries. For example, any American can make a call from here to U.S.A.. and in U.S.A. for that call the subscriber of that telephone will pay. But if you are visiting U.S.A. you cannot make a call from there to your hear and dear ones in India because the credibility of our country is not acceptable to the world telephone system. They feel that India will not pay. It is not important whether it is allowed to an individual or not allowed to an individual. This is a question of credibility of our country. When we allow the Americans to make call from here to U.S.A. or to any other developed country, we should also have the same privilege ; otherwise that privilege should be stopped to them also. That will be more equitable.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे संचार मंत्री जी ने ग्रुप डायलिंग सुविधा प्रदान करने के लिए विस्तृत वक्तव्य दिया है, उससे इनके मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा न हुई हो इस सदन में लेकिन उसकी पूर्ति इस वक्तव्य के माध्यम से हो गई है। ग्रामीण परिवेश का नेतृत्व करने वाले संचार मंत्री जी अग्रण्य लोगों में हैं जो इस देश के गांवों की सुविधा का किसानों का ध्यान रखते है और जो काम दिया जाता है उसमें ग्रामीणों को विशेष लाभ हो क्योंकि भारत गांवों का देश है, उस काम को करते है । जैसे इनकी शलाघनीय योजना है टेलीफ़ोन एक्सचेंज जो ग्रामीण क्षेत्रों में अब 15 हजार हो गये हैं 8 हजार से और 1995 तक साढ़े सत्ताईस गुना जो 1982 में था, वह करने का इनका संकल्प है, इसकी पूर्ति में यह लगे हुए हैं। टेक्नीकल चीजों के विस्तार में न जा करके क्योंकि समय की पाबंदी आपने लगा दी है, इसलिए मैं केवल तीन चार चीजों की ओर अपनी जिज्ञासा प्रकट करुंगा। मैं वाराणसी का रहने वाला हूं। इंदिरा जी के समय में हवा एक इलेक्ट्रोनिक एक्सन्चेज बनाने के लिए एक सात मंजिली बिल्डिंग का प्रस्ताव आया। उसके लिए जमीन खरीदी गई, इक्विपमैन्ट का भी प्रावधान किया गया लेकिन आज तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि क्या 31 मार्च, 1995 तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज आप लगाना चाहते हैं और छोटी-मोटी बिल्डिंगों में वे लगाते हैं तो यह शलाघनीय योजन इंन्दिरा

जी ने बनाई थी, क्या उसकी पूर्ती को टाइम बाउंड करने के लिए आप कोई काम करने जा रहे हैं ? दूसरा आपकी टेलीफोन इंडस्ट्री 6 भागों में देश में बढ़कर काम कर रही है। इसमें एक हमारे मनकापुर में है उसे देखने का उसे अवसर मिला । करीब आधा मील में हमारा मुडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है संचार का बड़ी तेजी से और वहां के लोगों ने, कर्मचारियों ने अधिकारियों ने मुझे बताया कि सारी छहों जो ये टेलीफोन इंडस्ट्रीज है इनको आप बैंगलोर के मातहत करना चाहते हैं। इन छहों की आटोनामी बनी रहे और किसी के मातहत न हो बल्कि मिनिस्ट्री के मातहत हों और सब अपने काम प्रतिस्पर्धा से करें । इस पर आश्वासन तो आपने दिया था मुझे कि मैं इस चीज को करूंगा कि सबकी आटोनामी बनी रहे और सब प्रतिस्पर्धा से काम करें । तो क्या इस पर निश्चय कर लिया है कि छहों की अपनी इंडिवीजुअलिटी बनी रहे, सबका अस्तित्व बना रहे ? . . . (**समय की घंटी**) दो प्वाइंट और हैं ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मैं बताना चाहता हूं, कि चंदोली में वहां बनारस के टेलिफोन के अधिकारियों ने बताया कि 20 टेलीफोनों के लिए एप्लीकेशंस आ जाएं । वहां टेलीफोन एक्सचेंज है, पुराना है तो उसको वे इलेक्ट्रानिक कर सकते हैं । जो अभावग्रस्त इलाके हैं गांवों के उनमें टेलीफोन की प्रवृति जागृत करने के लिए-जैसे शुरू शुरू में इस देश में चाय नहीं पीते थे लोग चाय की आदत लगायी लगी, उसी तरह से टेलीफोन हैबिट डेवलप करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं उन ग्रामीण इलाकों में जो गरीबी रेखा से नीचे जिंदा रहना चाहते है। उनको कैसे इससे आप जोड़ना चाहते हैं । टेलीफोन की सुविधा और फाल्स बिल्स की बात हुई है । मैं बड़ी विनम्रता के साथ मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहां पावर मिनिस्टर श्री कल्पनाथ राय जी से हमने एक प्रश्न के तहत पूछा कि क्या सांसदों को टेलीफोन का बिल नहीं आएगा । तो उन्होंने कहा था . . . (**समय की घंटी**) असली बात पर मैं आ रहा हूं माननीय उपसभाध्यक्ष जी, तो उन्होंने कहा था कि यहां राज्य सभा के लीडर बैठे हुए हैं, ये भी सुन रहे हैं और मैं प्रधान मंत्री तथा कैबिनट तक इस चीज को ले जाउंगा क्योंकि बहुत से प्रांतों में असेम्बलीज के मेम्बर्स को बिजली का बिल नहीं आता है । इससे टेलीफोन बिल देने की चिंता मंत्रियों को नहीं रहेगी । फाल्स बिल्स आते या सही बिल आते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि बहुत अधिक फाल्स बिल्स आते होंगे, कभी कभी आते हों लेकिन टेलीफोन की फ्री सुविधा हो एस. टी. डी और लोकल काल्स की । आप किसानों के हमदर्द है, हम सांसदों की भी हमदर्दी आपके पास है । कोई बिल सांसदों को न आए क्या ऐसा क्रांतिकारी कदम आप उठायेंगे इसका मैं आश्वासन आपसे चहता हूं . . (**व्यवधान**) बिल देने की चिंता रहेगी तो क्या करेगा आदमी।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० नारायणसामी) : श्री सलारिया जी । दो मिनट

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): First of all, 1 would like to congratulate the hon. Minister for this very laudable and adventurous scheme which he has given. I have all good wishes for him for bringing it to a conclusion so that the country is benefited. Sir, the existing system is not good and the result is that for many days the telephone remains out of order. Sir, I want that there should be a system by which no money should be charged for the period for which the telephone does not work, either rental or any other charge. My second question is about (he resolution of disputes between the subscribers and the department. The present system has an arbitration clause. This is very combersome and it takes a very long time. I would like to know whether the hon. Minister would consider ways and means to bring about an amendment in the legislation so that if there is any difference or any complaint with regard to charges; that cunbe settled. Now coming to the

[SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA]

scheme, it is very laudable that the hon. Minister has said that the charges for direct dialling facility within the SDCA shall be concessional at Rs. 1 for every three minutes in case of rural exchanges. But my submission is that the trunk call charges for these exchanges have been raised from Rs. 2 to Rs. 5 which is excessive .... *(Interruptions)* Mr. Sahu can talk to the Minister afterwards. I want the attention of the hon. Minister to this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY! : The Minister is hearing you.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : I submit that the enhancement of the rate from Rs. 2 to Rs. 5 for one call unit in rural areas is excessive. He may consider to reducing it and making it from Rs. 2 to Rs. 3 instead of Rs. 5. Then, coming to page 4 of his statement,, he says that in all systems of more than 30,000 lines capacity, five minutes will be the maximum duration which will be metered @ one call unit. If it exceeds five minutes, then he will be charged for another five minutes, whether he uses it for five minutes or not. May I request the Minister that for every one minute in excess of five minutes, he should be charged Re. 1 instead of a flat rate of Rs. 5 ? Will he consider that after five minutes, every minute will be separately chanrged ?

Then it is said that the fax machines and computers hold up the lines for a long time. Generally the normal subscribers do not hold up the line that long. They limit it to three minutes. Therefore, the increase in the rate should be applicable only to the fax machines and computers and not to others who do not use the line for long durations.

SHRI SOM PAL (Uttar Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir I congratulate and compliment the Communications Minister for revolutionising the communication system of India, particularly the rural India, and integrating the whole nation on the communication network. Many facilities have been allowed by the Communications Department like dynamic STD code, conference within the exchange and between one exchange and another, hotlines within the exchange and many other facilities which are very welcome features of the communication system. All of them are very efficiently operating, at least in cities like Delhi where electronic exchanges are functioning. But in granting these facilities, the Department has been showing a very callous attitude and all the users have been harassed and embarrassed. I will cite my own case. My own telephone—it is in my name—bearing number 5501770—if you wish, I can write to you—was shifted about a year back. But so far a new apparatus has not been provided to me. I am using an old instrument which was lying with me when I shifted my business and I am managing with it. This is my personal experience. And I say this will full responsibility. Two : Delay in shifting this very telephone. Even after the issuance of the OB number, it took more than a year and I had to go to the office thrice. Only after issue of the OB a third time that this telephone was shifted. Third : I had sought the provision of dynamic STD code more than six months ago from the Area Manager (West) for my other telephone No. 5555366. My house is in Janakpuri. This telephone is in my father's name. This has not been provided so far. There is a phone in Sarita Vihar which belongs to one of my cousions. I had requested the honourable Minister and he assured me— and the language used by Mr. Pilot in his letter was— that it had been ordered to be shifted immediately in February, and still it has not been implemented. I will give you the photocopy of that letter; I am not carrying it with me just now.

Fourthly, there is a phone in the name of my wife and the number is 6449489.

SHRI RAJESH PILOT : You have so many phones!

SHRI SOM PAL: She has a business and it is in South Extension. She had applied for a dynamic STD code and three times the letter came back saying that the signature did not tally and I as a Member

of Parliament had to certify that. It could be verified on phone. What is the use of having such a communication system where you need letters to travel for six months and still it is not being implemented and nothing is done ? It is a very small matter and there is unnecessary harassment.

I would like the honourable Minister to consider all these things. When he is revolutionising the whole system, at least let him have a look at the procedures. Once these things are applied for, there should be some time-limit and it should be seen that within that period all these are granted. 1 say this because this will create additional revenues for the Department and it will earn them goodwill also and reduce the difficulties of the subscriber in a big way.

There is another fact which has come to my notice and it is that certain machines have been developed abroad and imported in India by certain private citizens which can doze the meter. I would like to know whether the Minister has come across such information and, if he has not, let him kindly check up.

Then, there is a racket which is going on and to which everybody has referred. I made a call to Mekrana about three months back and, after a month of that call, I received a call from the Cannaught Place Trunk Exchange. A lady called me and asked me whether I wanted to make trunk calls very frequently. I do not want to mention her name because, otherwise, she may be hurt. She said that if it was so, I could have an arrangement for ten rupees within a few minuutes. If you wish, I can give you the name.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Yes, Mr. Chhotu-bhai Patel.

श्री छोटुभाई पटेल (गुजरात) : सर, यह नाइनटीज डिकेड में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है और खुशी की बात है कि यह कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक सक्षम हाथों में अब चल रहा है । उपसभाध्यक्ष जी The statement has been drafted very nicely. The statement itself speaks of the competence and efficiency of the honourable Minister.

मैं इसमें न एडीशन करना चाहता हूं, न आल्टरेशन करना चाहता हूं और न डिलीशन करने की जरूरत मझे लगती है। The planning and programme made by the. honourable Minister has been made with total intelligence. I would like to know from the Minister whether he is going to implement this Group Dialling System work efficiently.

आप सक्षम हैं, तो मैं चाहूंगा कि यह सिस्टम जो है सारे देश में पूरी सक्षमता से आप अमलीकरण करायेंगे । नंबर दो, सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके डिपार्टमेंट में आप लाग करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? Thirdly, there are so many families which are staying abroad.

प्रतिशत भी वह संतुष्ट नहीं है तो मैं नवसारी में ई 10 बी एक्सचेंज आप मैनुअल की बजाए लगाने जा रहे हैं तो अभी जो मैनुअल एक्सचेंज वहां है तो 50 प्रतिशत जो रहते है उसको आप सन्तुष्ट कर पायेंगे ? मैं चाहूंगा कि इस नवसारी के बारे में आप पूरा ध्यान देंगे और वहां की जनता को सन्तुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे ।

दोबारा मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं ।

श्री शान्ति त्यागी : माननीय वाईस चेयरमैन, ग्रामीण भारत को माननीय संचार मंत्री जी से बड़ी आशाएं हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आशाएं ग्रामीण हिन्दुस्तान की वह पूरी करेंगे और जो योजना आज ग्रुप डायलिंग फैसिलिटी की उन्होंने इसी सदन में रखी है वह इस बात की निशानी है और गारंटी है कि वह ग्रामीण क्षेत्र में टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क का आइंदा आने वाले टाइम में पूरा जाल बिछा देंगे ।

यह विश्वास लेकर में चल रहा हूं । मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ ही यह

[श्री शांति त्यागी]

भी कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आप तो देहात में घूमे हैं, आपने देखा है कि वहां किस तरह से बिजली की लाइंस लगी हुई है, उनके खंभे गढ़े हैं ? वहां लगे बिजली के तार भी आपने देखे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कि वे ढीले-ढाले लटके हुए हैं । इसलिए माननीय मंत्रीजी मैं आपसे यह कहूंगा कि जब इतना बड़ा नेटवर्क आप खड़ा कर रहे हैं तो आप आपने विभाग के लोगों को कहें और मुझे आशा है कि आप कहेंगे कि ये लाइंस टेंपरेरी नहीं है । आइंदा जो भारत आप बना रहे हैं, उसमें ये लाइंस मुस्तकिल हैं और इसलिए आप खंभों का और तारों का काम ऐसा कराएं कि वह एक सदी तक काम दे यह नंबर एक बात हुई । दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि लाइंस में फाल्ट होंगे, अपरेटस में फाल्ट होंगे; एक्सचेंज में फाल्ट होंगे बड़ी मशीनरी आप इन फाल्टस को ठीक करने और काफी वाली खड़ी करेंगे । इस सबके लिए आप पूरा इंतजाम करेंगे यह मैं आपसे आशा करता हूं ।

अंत में एक छोटा सा सवाल यह करना चाहता हूं कि आपने यह ग्रुप डायलिंग स्कीम शुरू की है । मैंने इसे पढ़ा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इसकी डिफिनीशन क्या है इन टर्मस आफ विलेजेज; इन टर्म्स आफ उपभोक्ता, इसे आप कुछ भी कहिए, यह अभी तक समझ में नहीं आयी है । उसे आप क्लैरीफाय करें और जो लाइंस खींचनेवाली बात और बाद में फाल्ट आएंगे एक्सचेंज में भी आपरेटस में भी तो उनको ठीक करने की मशीन भी खड़ी करनी चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने ग्रामीण भारत की लाज रखी उसके विकास के लिए इंतजाम किया ।

कुमारी सईदा खातून (मध्यप्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को दो-तीन सुझाव देते हुए यह कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्रीजी से कि संशोधित योजना के साथ-साथ एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव आप बता रहे है जिसके जरिये एक-दूसरे के आस-पास स्थित और एक सीमा वाले दो टेलिफोन प्रणालियों के उपभोक्ता कम दर पर अपनी बातें कर सकेंगे, तो माननीय मंत्रीजी को मैं यह सुझाव दूंगी कि यह स्कीम जब आप शुरू करेंगे तो हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव जी के जन्म दिन, 20 अगस्त तक अगर आप यह स्कीम शुरू कर दें तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे ....**(व्यवधान)**... नहीं, शुरू कहां हुई है ? उन्होंने बताया है कि यह संशोधित प्रसारण योजना के साथ-साथ एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव भी इनके सामने है

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जैसे कि हम कंजयूमर्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं । आपके विभाग में भी कंजूमर्स को प्रोटेक्शन मिलता है । मैं खुद भी कंजूमर्स प्रोटेक्शन काउंसिल की मेंबर हूं । तो हम लोग टेलिफोन विभाग और दूसरे विभागों में कंजूमर्स प्रोटेक्शन की बात करते हैं, पर हम एम० पी० लोग भी कंजूमर्स है और भले ही हम कंजूमर्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लेकिन हम भी आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं क्योंकि हम एम० पीज० के पास और खास तौर से लेडीज एम० पीज० के पास काफी धड़ाके से बिल आए हुए हैं । दो लाख से लेकर, चार लाख व आठ लाख तक के बिल आए हुए हैं जबकि हम लोगों को इतनी फुर्सत ही नहीं रहती टेलिफोन पर बात करने की इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं । धन्यावाद ।

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कुछ समय पहले मैंने अखबारों में पढ़ा था कि आप एक वाइस मेल बाक्स स्कीम शुरू करना चाहते हैं जिसके द्वारा आप उपभोक्ता को बिना टेलिफोन लिए ही टेलिफोन की सुविधा देना चाहते हैं जिसमें कि आप एक्सचेंज में एक आम जनता को बिना टेलिफोन लिए एक नंबर

देंगे जोकि कोई भी यूज कर सकता है और वहां पर मैसेज छोड़ सकता है और फिर आम जनता वहां से मैसेज ले सकती है बिना टेलिफोन लिए। तो इस तरह की क्या कोई स्कीम है? यदि है तो वह क्या स्कीम है और कब से उसे शुरु करने जा रहे हैं और वह कहां-कहां होगी, क्या शहरों में ही होगी या गांवों में भी होगी ? इस तरह की स्कीम आप कब तक लागू करेंगे, यह मैं जानना चाहूंगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय संचार मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत के गांव के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए टेलीफोन की सुविधाओं के माध्यम से एक जबरदस्त सहयोग दिया है और इस सहयोग से धन की बचत हुई है, समय की बचत हुई है। यह टेलीफोन के माध्यम से एक ऐसी सुविधा गांव को दी गई है, जिसकी वजह से हमारे ग्रामीण भाइयों की काफी प्रगति होगी और जल्दी होगी। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और हमारे आदरणीय पी. वी. नरसिंह राव जी को भी बधाई देता हूं कि उनकी मंशा के अनुसार आदरणीय पायलट जी ने यह क्रांतिकारी कदम उठाए हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से तीन-चार बिन्दुओं पर क्लेरीफिकेशन चाहता हूं उन्होंने बताया है कि मार्च, 1995 तक, देश में जो 2 लाख 20 हजार के करीब पंचायतें है, उनको यह सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं। तो जैसा आपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वर्ष 1982 में 8,000 एक्सचेंज ग्रामीण अंचल में थे और वर्ष 1992 में वह 15,000 हो गए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1995 तक कितने एक्सचेन्जेज की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है ? और, क्या यह उस समय तक उपलब्ध हो पायेंगे ?

दूसरा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यहां आपने यह संकल्प लिया है कि प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर आप टेलीफोन की सुविधा मार्च, 1995 तक पहुंचाने जा रहे हैं, वहीं यह प्रावधान करने की कृपा करें कि एक हजार और उससे ज्यादा की आबादी का अगर कोई गांव उस पंचायत विशेष में है तो उसको भी यह सुविधा प्रदान की जाए ?

इसके साथ ही जो हमारे आतंकवाद से समस्याग्रस्त राज्य हैं, जैसे पंजाब, कश्मीर और असम, इनके लिए न केवल पंचायत आतंकवाद हेडक्वार्टर में, बल्कि मैं निवेदन करूंगा और मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे, कि प्रत्येक गांव में यह सुविधा प्रदान की जाए ताकि उस समस्या के निदान में इस टेलीफोन के माध्यम से जो सहयोग प्रदान हो सकता है, वह प्रदान किया जा सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, जो खंबों की बात है और मेण्टीनेन्स की बात है, यह बात सच है और यह प्रश्न हमारे मन में भी है कि कार्यवाही त्वरित गति से चल रही है। मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि गांव के लोगों में बहुत उत्साह और खुशी है। आपके विभाग की जो गतिविधियां हैं और जो कार्यवाही चल रही हैं, उसके लिए मैं बधाई आपको दे चुका हूं और देता भी हूं। साथ ही मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि बाद में मेंटीनेन्स के मामले को लेकर कुछ अधिकारी, कर्मचारियों की ढिलाई के कारण जो कार्य ठीक से नहीं हो पाता, तो मैं चाहूंगा कि जैसे मंत्री महोदय स्वयं चुस्त है, वैसे ही अपने विभाग को बनाकर इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। इसमें भी मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं।

अन्त में, महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सुविधा उन्होंने गांवों को दी है, इसी प्रकार की सुविधा शहरों को दें ताकि उसके माध्यम से

[श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर]

जितने भी लोग टेलीफोन चाहने वाले हैं, उन सबको मिल सके क्योंकि लोग इसे अपने किराए पर लेना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कब तक आप यह संपूर्ण सुविधा भारत के लोगों को प्रदान करने जा रहे है ? धन्यवाद।

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa) : Sir, I would like to seek a clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Already, 21 Members have sought clarifications.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Sir, please allow him. He comes from a rural area. We all support him.

SHRI SARADA MOHANTY : This statement is in regard to telecommunications. I would like to know from the hon. Minister as to when he is going to come forward with a statement on postal services. What measures is he taking in regard to postal services ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : This is about telephone. How can you seek clarifications on postal services here ? Now, the hon. Minister please.

SHRI RAM AWADHESH SINGH (Bihar) : Sir, just one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : You were not there when your name was called. Please take your seat. I have already called the Minister. Mr. Minister please.

श्री राजेश पायलट : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने अपने विचार और बहुत अच्छे सुझाव दिए। ज्यादातर एक बात जो शांति त्यागी जी कह रहे थे कि हम समझ नहीं पाए कि ग्रुप डायलिंग क्या है ? उपसभाध्यक्ष जी, जैसे 6-7 एक्सचेंज किसी इलाके में हों, चाहे वह एक जिले में हों या दो जिलों में हों क्योंकि टेलीफोन एक्सचेंज के डिस्ट्रिक्ट जरूरी नहीं है कि रिवेन्यु डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हों। आज क्या होता है कि 6-7 एक्सचेंज एक जिले में हैं, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज तक बुक करना पड़ता है कि आप फलां जगह से फलां जगह तक के लिए काल बुक करें और फिर वह काल जब आती है तो बात होती है। यह सिस्टम जो हम ला रहे हैं इससे उन 6-7 एक्सचेंजों में डायरेक्ट डायलिंग हो जाएगी, आप एक जगह से दूसरी जगह पर सीधे बात कर सकेंगे। हम यह सुविधा देने जा रहे हैं क्योंकि काल बुक होती है तो मिलती नहीं है और फिर उसमें चार्जिज में भी गड़बड़ होती है और इससे एस० टी० डी० गांव तक जल्दी पहुंचेगी।

श्री शान्ति त्यागी : बहुत देर के बाद बात समझ आई।

डा० राजेश पायलट : मुझे भी बहुत देर में समझ आया था।

उपसभाध्यक्ष जी, तीन-चार मोटी-मोटी बातें हुई। एक तो सभी मैम्बरान ने कहा कि जहां इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज नहीं है, वहां यह कैसे होगा ? मैंने खुद कहा है कि यह सिस्टम सिर्फ इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज जहां पर हैं, वहीं पर डायनामिक लॉक की बात हुई और मीटरिंग की बात हुई। यह ज्यादातर वहीं हो पाएगा जहां इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज है।

एक बात टाइम के बारे में कही माननीय सदस्यों ने। हर जगह शिकायत थी कि हर बार काल इन्गेज मिलती है, जैसे हमारे माननीय सदस्य अहलुवालिया जी कह रहे थे कि हर बार जब डायल करो तभी यह खबर आती थी कि बहुत व्यस्त है। उसके और भी कारण हो सकते हैं, एक कारण यह होता है कि हम लोग जब टाइम की लिमिट नहीं है तो काफी देर तक लोकल एक्सचेंज इन्गेज रखते हैं। 5 मिनट हमने यह सोचकर रखा कि टेलीफोन पर 5 मिनट किसी भी काम के लिए काफी है। मैं भी

समझता हूं कि हिन्दुस्तान में आज सभी भाइयों के पास फोन नहीं है, कभी पड़ोस में फोन करना पड़ता है तो बुलाने के लिए लोग चले जाते हैं, जब वह आता है तब बात होती है, यह सोचकर हमने 5 मिनट रखा। रिकमेंडेशन 3 मिनट की थी लेकिन सभी माननीय सदस्यों का मन था कि 5 मिनट कम से कम हों तो हमने 5 मिनट से शुरुआत की हैं, आगे देखेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता अगर सुविधा हुई तो। पीक आवर पर हमारी सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, जब पीक ऑवर होते हैं तो उस वक्त सारी लाइनें इन्गेज चलती हैं। दूसरे देशों में सिस्टम है कि पीक ऑवर में चार्जिज ज्यादा होते है और जो लीन आवस है, उन पर थोड़े काम होते हैं, पर हमने अभी शुरू नहीं किया। हमारे देश में अभी यह सिस्टम चल नहीं पाएगा, हमने उस सिस्टम को अभी यह सिस्टम इग्नोर किया।

एक सबकी शिकायत बिल की थी कि बिल ज्यादा आते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि बिलों में कहीं न कहीं गल्तियां हैं। कहीं कुछ स्वाभाविक भी है और कहीं हम लोग महसूस नहीं करते कि हमने कितनी देर बात की। जब बात करते हैं तो महसूस नहीं करते कि एस० टी० डी० का मीटर चल रहा है, लेकिन जब बिल आता है तो एकदम कहने लगते हैं कि साहब यह बहुत हो गया। तो एस० टी ०डी० डायनमिक लाक हमने इसलिए दिया है और मैंने डिपार्टमेंट में यह आदेश भी दिये हैं कि कोई भी भाई अगर डॉयनमिक लॉक चाहे एक्सचेंज का तो उसको दिया जाए, पर यह सिर्फ हम वहीं लगा सकते हैं जहां इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज का नम्बर हो और सारे देश में हर जगह टोटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज नहीं है। दिल्ली जैसी जगह में भी 100 प्रतिशत इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज नहीं है, यहां भी 70-75 परसेंट के करीब हैं। उम्मीद है कि अगले साल, डेढ़ साल में यहां 100 % इलेक्ट्रानिक एक्सजेंज हो जाएंगे। जहां तक मीटरिंग का सवाल है, हमारे डिपार्टमेंट से आज भी छूट है किसी भी सब्सक्राइबर को कि वह अपना मीटर अपने आप लगा ले, लेकिन मीटरिंग हमारे एक्सचेंज की होगी क्योंकि टेम्परिंग हो सकती है। जहां तक बिजली के बिल के मीटर की बात कही, गांव में, उपसभाध्यक्ष जी, क्या करते हैं कि कहीं-कहीं मीटर तो लगा रहता है लेकिन वह तार से सीधी बिजली ले लेते हैं, मीटर तक तो पहुंचने भी नहीं देते उसको। लेकिन फिर भी इन हालात में हम लोग इजाजत दे देंगे कि कोई भी भाई अपना इलेक्ट्रानिक मीटर लगाए, कम से कम चैकिंग के लिए तो सुविधा होगी कि हमारा बिल अगर एक लाख का है और उसका बीस का है तो हम पता कर पाएंगे कि गलती कहां है। वैसे आज सिस्टम यह है कि किसी भी सब्सक्राइबर को अगर 6 महीने तक 20 या 25 हजार तक बिल आता रहा है और उसको अगर एकदम से एक लाख का बिल आ जाए तो हमारा कानून है कि आप 20-25 हजार जमा करा दो और बाकी 70-75 हजार रुपया डिस्कशन के लिए फैसले के लिए डाल दो। हम एक लाख रुपया के लिए कभी जोर नहीं देते कि पहले एक लाख रुपया तुम जमा करो फिर बात करेंगे।जो पांच-छः महीने का औस्तन बिल हो एवरेज बिल हो उसको हम मानते हैं। यह भी सही बात है कि अगर 20-25 हजार रुपये का बिल हर महीने आए और फिर एकदम से किसी महीने दो लाख का आ जाए तो वह सब्सक्राइबर पर जोर वाली बात रहती है।

अगली बात कुछ लोगों ने मानिटरिंग की कही। भाई राम नरेश यादव जी ने कहा कि ये सब चीजें है तो बहुत अच्छी लेकिन मानिटर करनी बहुत जरूरी हैं। हम लोगों ने मानिटरिंग डिपार्टमैंट में शुरू की और हर सर्कल में मानिटरिंग की और इसका इतना असर पड़ा उपसभाध्यक्ष जी, कि आजादी के बाद कभी एक, साल में 4 लाख 50 हजार या 4 लाख 80 हजार से ज्यादा कनेक्शन कभी देश में नही लगे, लेकिन हर जिले पे मानिटर किया, हर सर्कल पे मानिटर किया और इस साल हमने 7 लाख 32 हजार टेलीफोन देश में लगाए

[श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर]

8.00 P.M.

जो सबसे बड़ा रिकार्ड था। जैसा अभी हमारे माननीय सदस्य भाई सुरेन्द्र जी कह रहे थे कि 31 मार्च, 1995 तक गांव-गांव में टेलीफोन लगाने का हमने एनाउंस तो किया, लेकिन 8 हजार से 15 हजार एक्सचेंज हुई है, तो आगे कैसे होगा? यह तो गांव की एक्सचेंज है जहां 20-20 टेलीफोन एक गांव में हैं। वह एक्सचेंज 8 हजार से 15 हजार हुई हैं। लेकिन हमने फैसला किया है कि इस देश के 100 गांव हम रोज के पी० सी० ओज० के साथ जोड़ते हैं और इतना बढ़ावा मिला उपसभाध्यक्ष जी, कि जब मैं मंत्री बना था और मैंने रिकार्ड पढ़े तो पिछले 45 साल में अब तक सिर्फ 42 हजार गांवों को हम जोड़ पाये थे। जब हमने आदेश दिया कि 100 गांव रोज के जुड़ेंगे और 31 मार्च, 1995 तक पूरे होंगे तो आज पिछले 6-7 महीनों में हम 22 हजार गांव जोड़ पाये हैं। 45 साल में कहां 42 हजार और अब 6-7 महीनों में 22 हजार। 100 गांव रोज जोड़ने की हमारी स्कीम चालू है। हर रोज मोनिटरिंग मंत्रालय में होती है और मैं खुद मोनिटरिंग करता हूं। जिस दिन मुझे 100 में से 80 नजर आते हैं तो उस दिन मैं लिख देता हूं कि 80 क्यों हुए। लेकिन जब कभी वे 500 कर देते हैं तो एक हफ्ते का वह पूरा कर देते हैं। आन दि ऐवरेज हम 100 को लेकर चल रहे हैं।

कुछ बात सन्तोष बागड़ोडिया जी ने कही कि जैसे दूसरे देशों में कलक्ट कॉल्स का सिस्टम है, हमारे यहां भी होना चाहिए। मुझे अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि यह क्यों नहीं है। मैं इसे देखकर माननीय सदस्य को डायरेक्ट जवाब दे दूंगा कि क्या कारण है और क्यों नहीं हो पा रहा है। रत्नाकर जी ने भी वही बात कही थी-विलेज पंचायत की, जो मैंने अभी जवाब दिया। दूसरे, वाराणसी एक्सचेंज के बारे में कहा है। मैं उसे व्यक्तिगत दिखलवाऊंगा और जो आई० टी० आई० की बात है उपसभाध्यक्ष जी, अभी 6 की 6 आई० टी० आई० सभी आटोनोमी बॉडी हैं। उनको खूब ऑटोनोमी दी गयी है। लेकिन एक साथ रखने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे यह हैं कि रिसर्च एंड डवलपमेंट जो इस सेक्टर में बहुत जरूरी है, अभी तो हम एक जगह रिसर्च करके 6 की 6 को सलाह दे देते हैं कि टैक्नोलोजी के बारे में ऐसा करो। अगर बिल्कुल अलग-अलग आटानोमी करके कहेंगे तो हर जगह इन्वेस्टमेंट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जितनी लेटेस्ट टैक्नोलोजीहै वह 6 की 6 में बराबर बांटकर हम लोग मौडर्न टेक्नोलोजी उन सब को दे रहे हैं और ऑटोनोमी देकर उन्हें और हक दे रहे हैं कि वह ज्यादा कर सकें।

भाई सलारिया जी ने कहा पांच मिनट का जो समय है वह बढ़ाना चाहिए। पांच मिनट का बहुत जेन्युअन और रिजनेबिल समय उन लोगों ने दिया है। ज्यादातर शिकायतें आई कि थोड़ें प्रोसीजर्स हमारे यहां अभी भी गलत हैं। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनके ट्रांसफर में ही एक साल लग गया। फिर एस० टी० डी० लॉक करने में टाईम लगा। हम इन प्रोसिजर्स को काफी हद तक सुधार रहे हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे विभाग ने एक सोशल ऑडिट पैनल की शुरुआत की है। इसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस भगवती जी, जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह, एयर मार्शल, एडमिरल चौपड़ा और डा० भास्कर राव हैं। इन पांच आदमियों का एक पैनल बनाकर और बी० जी० देशमुख जो रिटायर्ड केबिनेट सक्रेटरी हैं, इन सबका कांबिनेशन हमने किया है। इसमें टैक्नीकल आदमी भी हो, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, जुडिशियल भी हो और ब्यूरोक्रेट भी हो और यह सब मिलकर इनको टोटल पावर्स दी हैं कि कहीं देश के कोने में जायें और जहां लोगों की शिकायत हो और वहीं पर सरकार की तरफ से जो फैसला यह लेंगे, हम उसे मान्य करेंगे। इस प्रकार की हमने इनको पावर्स देकर सारे देश में जाने के लिये कहा है,

ोंकि कुछ बातें अभी हमारे पास तक सीधी
ीं पहुंच पाती । हालांकि हमारा विभाग ऑपन
ऊस डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर जो हमारे टेलीफोन
डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर, सर्किल लेबिल पर और
खुद भी सारे बोर्ड के आफिसर्स बोर्ड एंड पोस्टल
र्ड को लेकर स्टेट हैडक्वार्टर्स पर जाकर वहां
चीफ मिनिस्टर साहब से, वहां की पब्लिक
वहां के ब्यूरोक्रेट से जो डिस्ट्रिक्ट लेबिल तक
इल करते हैं उनसे सीधी बात हम करते हैं कि
पकी समस्या क्या है । हमारे लोकल आफिसर्स
ों होते हैं, कम्युनिकेशन बोर्ड के मेंम्बर्स वहीं
े हैं और मैंने पिछली बार मीटिंग में कहा था
जब आफिसर फील्ड में होते हैं तो रिकमण्ड
देते हैं और जब वही आफिसर हैडक्वार्टर्स
आ जाते हैं तो उसे रिलेक्ट कर देते हैं ।
। आफिसर अपनी रिकमण्डेशन हैडक्वार्टर्स में
कर अन-फिजिबिल कर देते हैं । तो यह
युनिकेशन गैप दूर हो जाता है जब हम आमने-
ने बात करते हैं। सारा टैलीकाम बोर्ड, चेयर-
और सारे बोर्ड, पोस्टल बोर्ड, हम वहीं
ै फैसले लेकर देश की समस्याएं दूर कर देते
जिससे कौरसपोंडेंस न हो और हमारी
स बराबर चलती रहे ।

ीणा जी ने वॉयस मेल बॉक्स के लिये पूछा
यह दिल्ली में जल्दी शुरू होने वाली है और
लोग चाहेंगे कि यह और जगह भी शुरू हो
। माननीय सदस्य सुरेन्द्र जी ने कहा कि पंजाब
ाम और जम्मू-कश्मीर में पंचायत ही तक
गांव-गांव तक हो । इन तीनों प्रदेशों के लिये
एक अलग टास्क फोर्स बनायी है । वहां
ाायोरिटी दे रहे हैं । हम उम्मीद करते हैं कि
ज्यादातर अगले एक साल; डेढ़ साल तक
गांव में हम लोग यह सुविधा दे पायेंगे
खासकर पंजाब, असम और जम्मू कश्मीर में ।
जम्मू-कश्मीर में हमारी हालत थोड़ी खराब है
लॉ एंड आर्डर सिचुऐशन की वजह से । इसलिए
उतना नहीं बढ़ा पा रहे हैं जितना हमारा
मन है ।

ज्यादातर सभी सदस्यों ने विभाग के बारे
में सहरानीय अलफाज कहे । मैं विभाग की
तरफ से उनका आभारी हूं और हम कोशिश
करेंगे कि उनका आशीर्वाद और गाइडेंस हमें
मिलती रहे ।

दूसरी बात रत्नाकर जी ने बिल की कही
हम लोगों ने एस० टी० डी० फैसिलिटीज दोनों
हाऊस में दे रखी हैं जब हाऊस चलता है और
जहां तक बाकी दिनों की बात है, वह पार्लिया-
मेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर के तहत आता है ।
मैं चाहूंगा कि रत्नाकर जी पार्लियामेंटरी
अफेयर्ज मिनिस्टर से बात कर लें । जो भी आदेश
होगा, उसे हम पूरा करेंगे ।

एक बात फिर मैं विभाग की तरफ से हाऊस
के सभी माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करता
हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरा
काम इस तरीके से करेंगे कि जो पब्लिक सर्विस
विभाग की तरफ से हो और पब्लिक यह महसूस
करे कि सेवा भावना, वर्किंग कल्चर में इतनी
इंप्रूवमेंट आए कि लोग उसकी सराहना करते रहें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : The House is adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at seven minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 13th May, 1992.